



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1468]
No. 1468]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2007/अग्राहायण 7, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2007/AGRAHAYANA 7, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2007

(आयकर)

का.आ. 2000(अ).—जबकि भारत में वर्ष 2006 के जून मास के 15वें दिन को हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार एवं कुवैत राज्य की सरकार के बीच अनुबद्ध करार, अक्टूबर, 2007 के 17वें दिन जो कि उक्त करार के अनुच्छेद 30 के अनुसार, इस करार के प्रभावी होने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात् परवर्ती अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि है, को प्रभावी होगा।

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि अनुबद्ध उक्त करार के सभी उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से भारत संघ में प्रभावी किए जाएंगे।

[फा. सं. 501/3/88-वि. क. प्र./अधिसूचना सं. 277/2007/वि. क. प्र.]

पूनम दत्त, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

कुवैत राज्य की सरकार

के बीच

करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा कुवैत राज्य की सरकार, आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्द्धन की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1**शामिल व्यक्ति**

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2**सम्मिलित कर**

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए गए करों पर लागू होगा, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं ।

2. सकल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगने वाले करों के रूप में माना जाएगा जिनमें चल और अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर कर और उद्यमों द्वारा अदा किए गए वेतनों और मजदूरियों की सकल रकम पर कर शामिल है ।

3. जिन वर्तमान करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं :

(क) भारत के मामले में :

- आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ;
(जिसे इसके बाद “भारतीय कर” कहा जाएगा);

(ख) कुवैत के मामले में :

- (1) निगतिम आय कर ;
- (2) कुवैती शेयर धारक कंपनियों के निवल लाभों से प्राप्त अंशदान जो विज्ञान में प्रगति के लिए कुवैत संस्था (के एफ ए एस) को देय हैं ;
- (3) जकत ;
- (4) राष्ट्रीय कर्मचारी कानून के समर्थन में लगाया गया कर (जिसे इसमें इसके बाद “कुवैती कर” कहा गया है)

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्त्वतः समान करों पर भी लागू होंगे, जो इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् किसी संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत विद्यमान करों के अलावा अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी क्रमशः अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अभिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- क) “एक संविदाकारी राज्य” तथा “दूसरा संविदाकारी राज्य” पद का अर्थ, संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा कुवैत राज्य से है ;
- ख) “भारत” पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र, और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर आकाशीय क्षेत्र के साथ-साथ अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के करार सहित भारतीय कानून तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं ;
- ग) “कुवैत” पद का अर्थ कुवैत राज्य के उस क्षेत्र से है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, कुवैत कानून के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है अथवा इसके बाद किया जाएगा जिस पर कुवैत अपने प्रभुसत्ता अधिकार अथवा क्षेत्राधिकारों का प्रयोग कर सकता है।
- घ) “व्यक्ति” पद में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय अथवा कोई अन्य सत्ता शामिल है। भारत के मामले में कोई ऐसी सत्ता जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई माना जाता हो ;
- ड.) “कम्पनी” पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में समझा जाता है ;
- च) “उद्यम” पद किसी भी प्रकार का कोई कारोबार करने पर लागू होता है।

- छ) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” तथा “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;
- ज) “अन्तरराष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है - किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;
- झ) “सक्षम प्राधिकारी” पद का अर्थ है :-
- (i) भारत के मामले में : केन्द्रीय सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
 - (ii) कुवैत के मामले में : वित्त मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- ञ) “राष्ट्रिक” पद का अर्थ है :
- (i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति ;
 - (ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारिता अथवा संगठन जिसे इसकी यह हैसियत संविदाकारी राज्य में लागू कानूनों से प्राप्त होती हो ।
- ट) “कर” पद का अर्थ भारतीय अथवा कुवैती कर जैसा संदर्भानुसार अपेक्षित हो, परंतु इसमें वो राशि शामिल नहीं होगी जो ऐसे करों के सम्बन्ध में ऐसी चूक अथवा त्रुटि के संबंध में देय है जिस पर यह करार लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदण्ड अथवा जुर्माने का द्योतक है ;
- ठ) “वित्तीय वर्ष” पद का अर्थ पहली अप्रैल से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से है ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो करों के प्रयोजनार्थ उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस समय था, जिस पर यह करार लागू होता है और उस राज्य पर लागू कर कानूनों के अंतर्गत यह अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा ।

अनुच्छेद -4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ “एक संविदाकारी राज्य का निवासी” पद का अर्थ :
 - (क) भारत के मामले में : किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसपर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध - स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी ऐसी ही कसौटी के कारण कर लगाया जा सकता है। परन्तु इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य के स्रोतों पर होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ;
 - (ख) कुवैत के मामले में, कोई व्यक्ति जो कुवैत अथवा भारत का निवासी हो और जो कुवैत में संबंधित वित्त वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 183 दिनों तक की अवधि हेतु वहां रहता है और कोई कम्पनी अथवा कोई सत्ता जिसे कुवैत में निगतिम किया जाता है, उस पर वहीं कर लगाया जाएगा ;
2. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, एक संविदाकारी राज्य के निवासी में निम्नलिखित भी शामिल होगा ;
 - (क) उस संविदाकारी राज्य की सरकार और उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा इसका कोई स्थानीय प्राधिकरण ;
 - (ख) सार्वजनिक नियम के तहत उस संविदाकारी राज्य में स्थापित किया गया कोई सरकारी संस्थान जैसे कि कोई निगम, केन्द्रीय बैंक, निधि, प्राधिकरण, संस्था, एजेंसी अथवा ऐसी ही अन्य सत्ता जो उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः पूर्ण स्वामित्व में हो और इसके द्वारा नियंत्रित हो।
3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :
 - क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

- ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;
- ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;
- घ) यदि उप - पैरा (क) से (ग) के उपबंधों के अंतर्गत उसकी हैसियत निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से इस का निपटारा करेंगे ।

4. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तब उसे केवल उसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध - स्थान स्थित है । यदि उस राज्य का जहां उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से इसे निपटाने का प्रयास करेंगे ।

अनुच्छेद -5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ “स्थायी संस्थापन” पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

2. “स्थायी संस्थापन” पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबंध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई शाखा ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ.) कोई कार्यशाला ;

- (च) कोई बिग्री स्थल ;
- (छ) कोई व्यक्ति, जो दूसरों को भण्डारण सुविधा देता है, के संबंध में कोई भांडागार ;
- (ज) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- (झ) कोई फार्म, बागान अथवा कोई अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों ।

3. कोई भवन अथवा कोई निर्माण स्थल, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप को तभी स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 12 माह की अवधि में कम से कम 183 दिनों से अधिक समय तक जारी रहे ।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अपने कार्मिकों अथवा उद्यम द्वारा ऐसे प्रयोजनार्थ रखे गए अन्य व्यक्तियों द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में सेवाएं उपलब्ध करवाना जिसमें परामर्शदात्री अथवा प्रबन्धकीय सेवाएं भी शामिल हैं, इन्हें स्थायी संस्थापन तभी माना जाएगा यदि इस प्रकार के कार्यकलाप 12 माह की किसी अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों तक अथवा इससे अधिक अवधि तक जारी रहें ।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

- (क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;
- (ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- (घ) उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

- (ड.) उस उद्यम के लिए मात्र कारोबार चलाने के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों ;
- (च) उप-पैराग्राफ (क) से (ड.) तक में उल्लिखित कार्य-कलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 9 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में किन्हीं ऐसी गतिविधियों के संबंध में स्थायी संस्थापन का होना तभी समझा जाएगा, यदि वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता हो, यदि यह व्यक्ति ;

- (क) उसे उस उद्यम की तरफ से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित न हों, यदि ऐसा कारोबार किसी निश्चित स्थान से किया जाए इससे उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ; अथवा
- (ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का एक स्टॉक आदतन रखता हो, जिसमें से वह नियमित रूप से उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की डिलीवरी करता हो ;
- (ग) वह आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में उस उद्यम के लिए या ऐसे उद्यम और अन्य उपायों के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया आदेश प्राप्त करता हो जो इस के द्वारा ; अथवा
- (घ) ऐसा करने में, वह उस संविदाकारी राज्य में माल का निर्माण करता हो अथवा उद्यम से सम्बन्धित माल अथवा पण्य-वस्तुओं का प्रसंस्करण करता हो ।

7. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, के अलावा जिस पर पैराग्राफ 9 लागू होता हो, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र में बीमे की प्रीमियम एकत्र करता है अथवा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

8. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम और अन्य उद्यमों की ओर से किए जाते हों जो इसके द्वारा नियंत्रित हों अथवा उनका इसमें कोई नियंत्रणकारी हित हो, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत स्वतन्त्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

9. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) से प्राप्त आय पर दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. “अचल सम्पत्ति” पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार; जलयानों, नौकाओं, वायुयानों और अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो अथवा करता रहा हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए हों।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की तब संभावना रहती है जब वह एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए किसी निश्चित और भिन्न उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार प्राप्त कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस संविदाकारी राज्य में उस राज्य के लागू कानूनों अथवा विनियमों के तहत किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र। अतः स्थायी संस्थापन द्वारा राशियों के संबंध में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा कमीशन के रूप में, निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न) यदि कोई हो, और अदा की गई हों तो उसके संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।

5. जहां एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसरण में होगा ।
6. शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि एक संविदाकारी राज्य के कर प्राधिकरण के पास किसी व्यक्ति के किसी स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ निर्धारित करने के लिए उपलब्ध सूचना अपर्याप्त हो, तब इस अनुच्छेद की कोई भी बात उस स्थायी संस्थापन की कर संबंधी देनदारी का निर्धारण करने के बारे में उस संविदाकारी राज्य के किसी कानून अथवा विनियमों को प्रभावित नहीं करेगी जिससे उस संविदाकारी राज्य के कर प्राधिकारी उन लाभों का आकलन कर सकें उस संविदाकारी राज्य के जिन पर कर प्राधिकारी द्वारा उस स्थायी संस्थापन में कर लगाया जा सके, बशर्ते कि कर प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियमों अथवा विनियमों को इस अनुच्छेद के सिद्धान्तों के साथ सतत रूप से लागू किया जाएगा ।
7. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हों ।
8. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।
2. यदि किसी जहाजरानी उद्यम का प्रभावी प्रबंध स्थान किसी जलयान पर स्थित हो, तब उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें जलयान का घरेलू बंदरगाह स्थित हो, अथवा यदि ऐसा घरेलू बंदरगाह नहीं है, तो उस संविदाकारी राज्य में जिसका जलयान का संचालन एक निवासी है ;

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- क) जलयानों अथवा वायुयानों के बेयरबोट आधार पर किराए से प्राप्त लाभ ;
- ख) आधानों के प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराए से प्राप्त लाभों, जिनमें माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन हेतु आधानों के परिवहन हेतु ट्रेलर और संबंधित उपकरण भी शामिल हैं ।

“जहां ऐसा किराया अथवा ऐसा प्रयोग, रख-रखाव अथवा किराया, जैसा भी मामला हो, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन के अनुरूप हो ।”

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से सीधी जुड़ी हुई निधियों पर ब्याज को जलयानों अथवा वायुयानों के ऐसे प्रचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा यदि ये ऐसे कारोबार के अनुरूप हों और अनुच्छे 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

5. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

6. यह स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद के उपबंध भारत गणराज्य की सरकार तथा कुवैत राज्य की सरकार के बीच 21 अप्रैल, 1982 को हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन से प्राप्त आय पर दोहरे कराधान के परिहार हेतु उपबंधों का स्थान लेंगे ।

अनुच्छेद - 9

संबद्ध उद्यम

1. जहां

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी मामले में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ हो, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी जो ऐसे लाभों का हितभागी स्वामी है को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, लेकिन, यदि लाभांशों का प्राप्तकर्ता हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। यह पैराग्राफ, उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें से लाभांश अदा किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी किसी अम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांश उस संविदाकारी राज्य में कराधेय नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी इस प्रकार हो -

क) सरकार, इसका कोई राजनैतिक उप प्रभाग अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई स्थानीय प्राधिकरण ;

ख) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेन्ट्रल बैंक, अथवा

ग) कोई सरकारी अभिकरण अथवा सरकारी वित्तीय संस्थान जिसे नामोदित किया जाए और जिसके बारे में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच टिप्पणियों का अदान-प्रदान कर सहमति हो सके।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “लाभांश” पद का अभिप्राय शेयरों, “ज्योइसेंस” शेयरों या “ज्योइसेंस” अधिकारों, खनन शेयरों, संस्थापन शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण के दावे न हों, लाभों में हिस्सेदारी से प्राप्त आय तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय है जिस पर वही कराधान अभिक्रिया लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध लागू होंगे ।

6. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य ऐसे मामलों को छोड़कर उक्त कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या उस दूसरे राज्य में किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी, जो ऐसे ब्याज का हितभागी स्वामी है, को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में जिसमें यह उद्भूत हुआ है । और उस राज्य के कानून के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा, किन्तु प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी कम्पनी द्वारा अदा किए गए ब्याज, जो एक संविदाकारी राज्य की एक निवासी है, उस संविदाकारी राज्य में कराधेय नहीं होगा, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी निम्न है :

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, किसी राजनयिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण ; अथवा

(ख) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेन्ट्रल बैंक ; अथवा

(ग) अन्य सरकारी अभिकरण अथवा वित्तीय संस्थान जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए तथा जिसके बारे में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच टिप्पणियों के आदान-प्रदान कर सहमति हो सके ;

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त ब्याज शब्द का आशय प्रत्येक प्रकार के ऋणदावे से प्राप्त आय से है चाहे वे बंधक द्वारा प्रत्याभूत हों या नहीं और चाहे उसे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी करने का अधिकार प्राप्त हो या नहीं, और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों और बाण्डों या ऋणपत्रों से प्राप्त आय से है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बाण्डों या ऋणपत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं, विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उत्पन्न हुआ तब माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां ऐसा ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ब्याज लिया गया था, जिस पर ऐसी आय की अदायगी की गई थी और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता हो तब ऐसा ब्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की राशि, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के आधिक्य भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “रायल्टियाँ” शब्द का अभिप्राय साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति, जिसमें टेलीविजन अथवा रेडियों के प्रसारण के प्रयोग हेतु सिनेमाटोग्राफ फिल्म अथवा फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, के कापीराइट का प्रयोग अथवा प्रयोग के अधिकार, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मुला अथवा प्रोसेस तथा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण अथवा संबंधित औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव प्रयोग अथवा प्रयोग के अधिकार हेतु प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी प्रकार की अदायगियां।

(ख) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” शब्द का अभिप्राय प्रबंधकीय अथवा तकनीकी अथवा परामर्शदात्री सेवाओं, जिसमें तकनीकी अथवा अन्य वैयक्तिक सेवाओं के उपबंध शामिल हैं, के प्रतिफल के रूप में इस करार के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित से भिन्न किसी प्रकार की अदायगियां।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबद्ध है ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीक सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे।

ऐसे मामले में, अदायगियों के उस आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 13

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा ।
3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयान अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयान के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा अंतरणकर्ता जिसका निवासी है ।
4. किसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक जिसकी सम्पत्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति शामिल है, के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ पर उस राज्य में कर लग सकेगा ।
5. किसी कम्पनी में, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिस में शेयर जारी करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।
6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित के अतिरिक्त किसी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, अंतरणकर्ता जिसका निवासी है ।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. किसी व्यक्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप के अन्य क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त आय उस संविदाकारी राज्य में तभी कराधेय होगी जब तक उसे अपने क्रियाकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है अथवा यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि किसी वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक अवधि अथवा अवधियों के लिए हो। यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसका कोई निश्चित स्थान अथवा ऐसा कोई प्रवास है अथवा था तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा परंतु केवल उतने हिस्से पर ही जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई हो अथवा उस राज्य में निष्पादित क्रियाकलापों से प्राप्त हुई हो।

2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक या शिक्षण संबंधी कार्यकलाप के साथ - साथ चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु - विदों, शल्य - चिकित्सकों, दन्त चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद - 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि ऐसा नियोजन किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है ; और

- (ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

4. कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का एक राष्ट्रिक तथा उस संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का एक कर्मचारी दोनों है, जिसका मुख्य कारोबार 'अन्तरराष्ट्रीय यातायात में एयरक्राफ्ट का संचालन है, तथा ऐसा व्यक्ति दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यों के संबंध में पारिश्रमिक प्राप्त करता है पर उद्यम में उसके सेवा नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियाँ जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य अथवा अन्य इसी तरह घटक के रूप में प्राप्त की गई हों, पर केवल उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 17

मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्त्ता या किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्त्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उन मनोरंजनकर्त्ताओं अथवा खिलाड़ियों जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी हैं, के दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित ऐसे व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उनके दौरे तथा कार्यकलापों का प्रथमोल्लिखित अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों जिसमें उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण अथवा उसका कोई सांविधिक निकाय शामिल है, के सार्वजनिक निधियों से पर्याप्त समर्थन किया जाता हो और न ही ऐसे कार्यकलापों के संबंध में गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्राप्त आय पर, बशर्ते कि इसके आय का कोई भाग इसके मालिकों, संस्थापकों अथवा सदस्यों को देय न हो अथवा उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए उपलब्ध न हो।

अनुच्छेद - 18

पेंशन और वार्षिकियां

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन एवं अन्य इसी तरह के पारिश्रमिक एवं वार्षिकियों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त :

क) “पेंशन एवं अन्य इसी तरह के पारिश्रमिक” शब्द का तात्पर्य पिछले सेवानियोजन अथवा अन्यथा पिछले सेवा नियोजन के संबंध में प्राप्त की गई जोखिमों की क्षतिपूर्ति के प्रतिफल के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद की गई आवधिक अदायिगयां।

ख) “वार्षिकी” शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति को जीवन के दौरान निश्चित समय पर अथवा एक निर्दिष्ट अथवा निर्धारित समयावधि के दौरान आवधिक रूप से देय नियत राशि अथवा धन या धन के समान पर्याप्त एवं पूर्ण प्रतिफल के लिए बाद में अदायिगयां करने की बाध्यता के तहत एक नियत राशि।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को अदा की गई पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगेगा।
- (ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हों और उक्त व्यक्ति उस राज्य का निवासी हो, जो :
 - (i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो ; अथवा
 - (ii) मात्र सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।
2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा उसके द्वारा सृजित निधियों में से या उस के द्वारा अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।
- (ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा, यदि उक्त व्यक्ति उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।
3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद - 20

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक अथवा शोधकर्ता, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य इसी तरह के संस्थान में अध्यापन करने अथवा शोधकार्य करने के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व संविदाकारी राज्य का एक निवासी है अथवा था, उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उस दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोधकार्य के लिए प्राप्त ऐसे किसी भी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।
2. यह अनुच्छेद केवल शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू होगा, यदि ऐसा शोधकार्य सार्वजनिक हित में किया जाता है और न कि मुख्यतया कुछ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए।
3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को किसी संविदाकारी राज्य का एक निवासी समझा जाएगा, यदि वह उस वित्तीय वर्ष में जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा उसके तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस राज्य का एक निवासी रहा हो।

अनुच्छेद - 21

विद्यार्थी तथा प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी अथवा प्रशिक्षु को जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से पहले किसी अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, और जो मात्र अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसे अपने भरण पोषण, शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्राप्त की गई अदायिग्यों पर उस संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगेगा।
2. पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के होते हुए भी, एक विद्यार्थी या प्रशिक्षु जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुरंत पहले अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और मात्र अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, द्वारा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रदत्त अस्थायी सेवाओं से व्युत्पन्न पारिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि ऐसी सेवाएं उसके शिक्षण अथवा प्रशिक्षण से संबंधित हैं तथा ऐसे सेवाओं से प्राप्त पारिश्रमिक उसके भरण पोषण के प्रयोजनार्थ उसे उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

3. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी समयावधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हों।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगी।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसे अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. किसी भी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानून, उन स्थितियों के अतिरिक्त संबंधित संविदाकारी राज्य में कराधान को शासित करते रहेंगे, जहां इस करार में इसके विपरीत प्रावधान किए गए हैं।
2. इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि इस अनुच्छेद के निम्नलिखित पैराग्राफों के अनुसरण में दोहरे कराधान का परिहार किया जाएगा :-

क) भारत के मामले में :

यदि भारत का कोई निवासी ऐसी आय अर्जित करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार, भारत और कुवैत दोनों में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की

आय पर कर से कटौती के रूप में उसके द्वारा कुवैत में अदा किए गए कर के बराबर की राशि की छूट दे सकता है ।

तथापि, दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती, आय पर कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिस की संगणना कटौती से पूर्व हो, जो उस आय के संबंध में हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर कुवैत में कर लगाया जा सकता है ।

ख) कुवैत के मामले में :

यदि कुवैत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत और कुवैत दोनों में कर लगाया जा सकेगा, तो कुवैत, उस निवासी की आय पर भारत में अदा किए गए आयकर की राशि के बराबर, कर से छूट की अनुमति प्रदान करेगा ।

तथापि, दोनों में से किसी भी मामले में ऐसी कटौती, आय के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसकी संगणना कटौती से पूर्व की गई हो, जो इसके कारण, जैसा भी मामला हो, ऐसी आय के संबंध में होगा, जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में अदायगी योग्य कर में उस कर को शामिल किया गया माना जाएगा जो अदायगी योग्य होता यदि उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रदान किए गए कर प्रोत्साहन न होते और जो अधिक विकास को प्रोन्नत करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं ।

अनुच्छेद - 24

संव्यवहार

1. किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाले वैयक्तिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न हो अथवा अधिक बोझिल हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाले व्यक्तियों पर उन्हें परिस्थितियों में विशेष रूप से निवास के संबंध में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक या दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो दूसरे राज्य के उद्यमों पर समान परिस्थितियों में समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू

होने वाले कराधान से कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को प्रदत्त कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे, जो अपने निवासियों को देता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कंपनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभों को कर की ऐसी दर पर प्रभारित करने से किसी संविदाकारी राज्य को रोकना है जो उस दर से अधिक हो जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के समरूप कंपनी के लाभों पर लगाया जाता है और न ही इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि यह इस करार के अनुच्छेद 7 के पैरा 3 के प्रतिकूल है।

3. ऐसे मामले को छोड़कर, जहां अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 का पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 का पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं, किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के तहत कटौती योग्य होगी, जैस कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हों।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का अर्थ एक संविदाकारी राज्य द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को किसी व्यवहार के लाभ, प्राथमिकता अथवा विशेषाधिकार देने की विधिक बाध्यता से नहीं है जो किसी तीसरे राज्य अथवा उस के निवासियों को किसी सीमाशुल्क संघ, आर्थिक संघ, किसी निर्बाध व्यापार क्षेत्र अथवा किसी क्षेत्रीय अथवा उप क्षेत्रीय व्यवस्था बना कर दिया जाए, जो पूर्णतया अथवा मुख्यतया कराधान अथवा पूंजी के संचलन से संबंधित हो, जिसका प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य एक पक्ष हो।

5. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, पर प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या उससे तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के समान उद्यमों, जिसकी पूंजी प्रथमोल्लिखित राज्य के एक या अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष या आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो या उनके अधीन हो पर लगाया जाता हो।

6. इस अनुच्छेद में, “कराधान” शब्द से तात्पर्य उन करों से है, जो इस करार के अध्यक्षीन हैं।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इन करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों पर ध्यान किए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः उस पर ऐसा कराधान लगाया जाता है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो ।
3. यदि इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो ।
4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । जब समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो तो उक्त संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन करके ऐसा आदान-प्रदान किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा इस करार के अंतर्गत आने वाले करों से संबंधित संविदाकारी राज्यों के आंतरिक कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक हों जब तक कि उसके अंतर्गत किया गया कराधान करार के प्रतिकूल न हो । सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उक्त राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें कोई न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के निर्धारण एवं उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध हों । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;
- (ख) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;
- (ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार संबंधी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, भेद प्रकट होते हों अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।

3. संविदाकारी राज्य राजस्व संबंधी दावों की वसूली में एक-दूसरे की सहायता प्रदान करेंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं होगी । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस पैराग्राफ को लागू करने के प्रकार को निर्धारित करेंगे ।

अनुच्छेद - 27**लाभों का परिसीमन**

किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी इस करार के लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, यदि उसके कार्य इस करार के लाभों को प्राप्त करने के प्राथमिक प्रयोजन से प्रबंधित किए गए हों। प्रामाणिक गतिविधि न रखने वाली कानूनी सत्ताओं का मामला इस अनुच्छेद के उपबंधों द्वारा सम्मिलित किया जाएगा।

अनुच्छेद - 28**विविध नियम**

1. इस करार के उपबंध का अर्थ अब तक या इसके बाद प्रदत्त किसी भी तरीके से किसी प्रकार के अपवर्जन, कटौती ऋण या किसी अन्य भत्ते को रोकना नहीं होगा, जो -

- क) उस संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए गए कर के निर्धारण में किसी संविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा दिए गए हों ;
- ख) संविदाकारी राज्यों के बीच आर्थिक या तकनीकी सहयोग के संबंध में कराधान संबंधी किसी अन्य विशेष प्रबंध द्वारा प्राप्त हों।

2. प्रत्येक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी इस करार के उपबंधों को लागू करने के लिए विनियम निर्धारित कर सकते हैं।

अनुच्छेद - 29**राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसूली पद**

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशन अथवा कौंसूली पदों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद - 30

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बारे में एक-दूसरे को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में अधिसूचित करेंगे।
2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचनाओं की तारीख को प्रवृत्त होगा।
3. जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके बाद अप्रैल माह के पहले दिन अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई आय के संबंध में इस करार के उपबंध प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद - 31

कालावधि एवं समापन

यह करार पांच वर्ष की अवधि हेतु जारी रहेगा और यह इसके बाद भी ऐसी ही अवधि अथवा अवधियों तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई एक आरम्भिक अथवा बाद वाली अवधि के समाप्त होने से छह माह पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य को लिखित में इस करार को समाप्त करने के लिए अपनी इच्छा की सूचना नहीं दे देता। ऐसी स्थिति में, यह करार दोनों ही संविदाकारी राज्यों में किसी वित्त वर्ष में अथवा जिस कैलेंडर वर्ष में यह सूचना दी जाती है उसके बाद अप्रैल माह के प्रथम दिन के बाद प्राप्त होने वाली आय के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके साक्ष्य में, दोनों संविदाकारी राज्यों के संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली, भारत में, उन्नीस जमाद अल अवल, 1427 एच के तदनुरूप वर्ष द्वा हज़ार छह के जून माह के पन्द्रहवें दिन हिन्दी, अरेबिक और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार
के प्रतिनिधि मण्डल की ओर से

हस्ताक्षर

शिवराज पाटिल
गृह मंत्री

कुवैत राज्य की सरकार
के प्रतिनिधि मण्डल की ओर से

हस्ताक्षर

बदर मिशारी अल-हुमैधी
वित्त मंत्री

प्रोटोकोल

भारत गणराज्य और कुवैत राज्य आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार हेतु करार पर नई दिल्ली, भारत में, उन्नीस जमाद अल अवल, 1427 एच के तदनु रूप वर्ष दो हजार छह के जून माह के पंद्रहवें दिन को हस्ताक्षर करते हुए इस बात पर सहमत हुए हैं कि निम्नोक्त उपबंध उक्त करार के अभिन्न अंग होंगे।

अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 और 2 के संबंध में यह माना जाता है कि जब एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है तब उस स्थायी संस्थापन के लाभ उस आय के भाग के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे जो ऐसी बिक्रियों अथवा कारोबार हेतु उस स्थायी संस्थापन की वास्तविक गतिविधि के कारण हुए हैं। उस संविदाकारी राज्य के, जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित हो उसके बाहर की गई बिक्रियों, कारोबार अथवा आपूर्तियों को उस स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह सर्वेक्षण, निर्माणों अथवा प्रतिस्थापनों हेतु संविदाओं के मामले में किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का संविदा की कुल राशि के आधार पर निर्धारण नहीं किया जाएगा, परन्तु इसका निर्धारण केवल संविदा के भाग के आधार पर किया जाएगा जिसे स्थायी संस्थापन द्वारा उस राज्य में प्रभावी रूप से निष्पन्न किया जाता है, जहां स्थायी संस्थापन स्थित हो। संविदा के उस भाग से संबंधित लाभ, जो उद्यम के प्रधान कार्यालय द्वारा किए जाते हैं, पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसका उद्यम कर्ता एक निवासी हो।

जिसके साक्ष्य में, दोनों संविदाकारी राज्यों के संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों ने इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली, भारत में, उन्नीस जमाद अल अवल, 1427 एच के तदनु रूप वर्ष दो हजार छह के जून माह के पंद्रहवें दिन हिन्दी, अरेबिक और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार
के प्रतिनिधि मण्डल की ओर से

हस्ताक्षर

शिवराज पाटिल
गृह मंत्री

कुवैत राज्य की सरकार
के प्रतिनिधि मण्डल की ओर से

हस्ताक्षर

बदर मिशारी अल-हुमैधी
वित्त मंत्री

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2007

(INCOME TAX)

S.O. 2000(E).— Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Kuwait for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed in India on the 15th day of June, 2006 shall come into force on the 17th day of October, 2007, being the date of receipt of the later of the notifications after completion of the procedures as required by the respective laws for the entry into force of this Agreement, in accordance with Article 30 of the said Agreement.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement annexed hereto shall be given effect to in the Union of India with effect from the 1st day of April, 2008.

[F. No. 501/3/88-FTD/Notification No. 277/2007-FTD]

POONAM DUTT, Jt. Secy,

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION

OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the State of Kuwait, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries,

Have agreed as follows:

Article 1**PERSONS COVERED**

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2**TAXES COVERED**

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
 - a) in the case of India:

the income tax, including any surcharge thereon;

(hereinafter referred to as "Indian tax");
 - b) in the case of Kuwait:

(1) the corporate income tax;

(2) the contribution from the net profits of the Kuwaiti shareholding companies payable to the Kuwait Foundation for Advancement of Science (KFAS);

(3) the Zakat;

(4) the tax subjected according to the Supporting of National Employees law. (hereinafter referred to as "Kuwaiti tax")

4. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed under the laws of a Contracting State after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India or the State of Kuwait as the context requires;

b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Agreement on the Law of the Sea;

- c) the term "Kuwait" means the territory of the State of Kuwait including any area beyond the territorial sea which in accordance with international law has been or may hereafter be designated, under the laws of Kuwait, as an area over which Kuwait may exercise sovereign rights or jurisdiction;
- d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons* and any other entity (which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States);
- e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- f) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;
- g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- i) the term "competent authority" means:
 - (i) in India: the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or its authorized representative;
 - (ii) in Kuwait: the Minister of Finance or an authorized representative of the Minister of Finance;
- j) the term "national" means:

Article 1**PERSONS COVERED**

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2**TAXES COVERED**

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
 - a) in the case of India:

the income tax, including any surcharge thereon;

(hereinafter referred to as "Indian tax");
 - b) in the case of Kuwait:

(1) the corporate income tax;

- (2) the contribution from the net profits of the Kuwaiti shareholding companies payable to the Kuwait Foundation for Advancement of Science (KFAS);
 - (3) the Zakat;
 - (4) the tax subjected according to the Supporting of National Employees law.
- (hereinafter referred to as "Kuwaiti tax").

4. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed under the laws of a Contracting State after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
- a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India or the State of Kuwait as the context requires;
 - b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Agreement on the Law of the Sea;

c) the term "Kuwait" means the territory of the State of Kuwait including any area beyond the territorial sea which in accordance with international law has been or may hereafter be designated, under the laws of Kuwait, as an area over which Kuwait may exercise sovereign rights or jurisdiction;

d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity (which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States);

e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;

g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

i) the term "competent authority" means:

(i) in India: the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or its authorized representative;

(ii) in Kuwait: the Minister of Finance or an authorized representative of the Minister of Finance;

j) the term "national" means:

- (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
 - k) the term "tax" means Indian or Kuwaiti tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;
 - l) The term "fiscal year" means the financial year beginning on the 1st day of April.
2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies and any meaning under the applicable tax laws of that State shall prevail over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means:
- a) in the case of India : any person who, under the laws of the State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State;

- b) in the case of Kuwait : an individual who is a Kuwaiti national or an Indian national and who is present in Kuwait for a period or periods totaling in the aggregate at least 183 days in the fiscal year concerned, and a company or an entity which is incorporated in Kuwait and is liable to tax therein.
2. For the purposes of paragraph 1, a resident of a Contracting State shall include all of the following:
 - a) the Government of that Contracting State and any political subdivision or local authority thereof;
 - b) any governmental institution created in that Contracting State under public law such as a corporation, Central Bank, fund, authority, foundation, agency or other similar entity, which is wholly owned and controlled directly by the Government of that Contracting State.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
 - a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 - b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
 - c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

- d) if his status cannot be determined under the provisions of sub-para (a) to (c), the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - a) a place of management;
 - b) a branch;
 - c) an office;
 - d) a factory;
 - e) a workshop;
 - f) a sales outlet;
 - g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;

- h) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources; and
 - i) A farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.
3. A building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities last 183 days or more in any twelve-month period.
4. The furnishing of services, including consultancy or managerial services, by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, in the other Contracting State constitutes a permanent establishment only if activities of that nature continue for a period or periods aggregating 183 days or more within any twelve-month period.
5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
- a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information for the enterprise;

- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
 - f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities, mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 9 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:
- a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph, or
 - b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise;
 - c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for such enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it;

d) in so acting, he manufactures or processes in that Contracting State goods and merchandise belonging to the enterprise.

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 9 applies.

8. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise and other enterprises, which are controlled by it or have a controlling interest in it, he shall not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

9. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not by itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6**INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY**

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7**BUSINESS PROFITS**

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State

through a permanent establishment situated in that other Contracting State. If the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed deductions those deductible expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with any applicable tax law or regulations of that State. Hence, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, charged or paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
5. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
6. For the removal of doubts, it is hereby clarified that if the information available to the tax authority of a Contracting State is inadequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment of a person, nothing in this Article shall affect the application of any law or regulations of that Contracting State relating to the determination of the tax liability of that permanent establishment by making of an estimate by the tax authority of that Contracting State of the profits to be subject to the tax of that permanent establishment by the tax authority of that Contracting State, provided that such law or regulations shall be applied, taking into account the information available to the tax authority, consistently with the principles of this Article.
7. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

8. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbor of the ship is situated, or, if there is no such home harbor, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.
3. For the purpose of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic include all of the following:
 - a) Profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft;
 - b) Profits from the use, maintenance or rental of containers, including trailers and related equipment for the transport of containers, used for the transport of goods or merchandise;

where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

4. For the purposes of this Article interest on funds directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft if they are incidental to the

- carrying on of such business, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.
5. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
 6. It is understood that the provisions of this Article shall replace the provisions of the Agreement between the government of the Republic of India and the Government of the state of Kuwait for the avoidance of double Taxation of income derived from international Air Transport Signed on 21st April, 1982.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of the State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner of such dividends may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State shall not be taxable in that Contracting State if the beneficial owner of the dividends is:

- a) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State; or
 - b) the Central Bank of the other Contracting State; or
 - c) other governmental agencies or governmental financial institutions as may be specified and agreed to in an exchange of notes between the competent authorities of the Contracting States.
4. The term "dividends" as used in this Article means income from shares including "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the

dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner of such interest may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, interest paid by a company which is a resident of a Contracting State shall not be taxable in that Contracting State if the beneficial owner of the interest is:
 - a) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State; or
 - b) the Central Bank of the other Contracting State; or
 - c) other governmental agencies or financial institutions as may be specified and agreed to in an exchange of notes between the competent authorities of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the

absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties or fees for technical services, arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.
3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or films or tapes used for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(b) The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 14 and 15 of this Agreement as consideration for managerial or technical or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable

according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State
5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in the State in which the company issuing the shares is resident.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities or if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding 183 days in the aggregate in any fiscal year. If he has or had such a fixed base, or such a stay in the other Contracting State, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base or income derived from activities performed in that State.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is

exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
 - b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.
4. An individual who is both a national of a Contracting State and an employee of an enterprise of that Contracting State the principal business of which is the operation of aircraft in international traffic, and such individual derives remuneration in respect of duties performed in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned Contracting State in respect of the remuneration derived from his employment with the enterprise.

Article 16**DIRECTORS' FEES**

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other state.

Article 17**ARTISTES AND SPORTSMEN**

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income derived by entertainers or sportsmen who are residents of a Contracting State from personal activities as such exercised in the other Contracting State if their visit to and activities in that other Contracting State are substantially supported from the public funds of the first-mentioned or both Contracting States including those of

any political subdivision, a local authority or statutory body thereof, nor to income derived by a non-profit making organisation in respect of such activities provided no part of its income is payable to, or is otherwise available for the personal benefit of its proprietors, founders or members.

Article 18

PENSIONS AND ANNUITIES

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration and annuities paid to an individual who is a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that Contracting State.
2. As used in this Article:
 - a) the terms "pensions and other similar remuneration" mean periodic payments made after retirement in consideration of past employment or by way of compensations for injuries received in connection with past employment.
 - b) the term "annuity" means a stated sum payable to an individual periodically at stated times during life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19**GOVERNMENT SERVICE**

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration and to pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20**PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS**

1. A professor, teacher or research scholar who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college or other similar institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.
2. This Article shall apply to income from research only if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the benefit of some private person or persons.
3. For the purposes of this Article, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.

Article 21**STUDENTS AND TRAINEES**

1. Payments which a student or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or

training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration which a student or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training derives from temporary services rendered in the first-mentioned Contracting State shall not be taxed in that Contracting State, provided that such services are in connection with his education or training and that the remuneration for such services is necessary to supplement the resources available to him for the purpose of his maintenance.
3. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is

effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation in the respective Contracting State except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article:

a) in the case of India :

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in both – Kuwait and India, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Kuwait.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the tax on income as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Kuwait.

b) in the case of Kuwait:

Where a resident of Kuwait derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in both –India and Kuwait, Kuwait shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in India.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the tax on income as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in India.

3. The tax payable in the Contracting State mentioned in paragraphs 2 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Individuals possessing the nationality of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which individuals possessing the nationality of that other Contracting State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, shall not be less favorably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that State, carrying on the same activities in the same circumstances. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its

own residents. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a Permanent Establishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State, nor being in conflict with the provisions of the Para 3 of Article 7.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4. Nothing in this Article shall be interpreted as imposing a legal obligation on a Contracting State to extend to the residents of the other Contracting State, the benefit of any treatment, preference or privilege which may be accorded to any third state or its residents by virtue of the formation of a customs union, economic union, a free trade area or any regional or sub-regional arrangement relating wholly or mainly to taxation or movement of capital to which such the first-mentioned Contracting State may be a party.
5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises the capital

of which is wholly or partly owned or controlled directly or indirectly by one or more residents of first-mentioned State are or may be subjected.

6. In this Article, the term "taxation" means taxes, which are the subject of this Agreement.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE,

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
3. The Contracting State shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

Article 27

LIMITATION OF BENEFITS

A resident of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of this Agreement if its affairs were arranged with the primary purpose to take benefits of this Agreement. The case of legal entities not having bona fide business activities shall be covered by the provisions of this Article.

Article 28**MISCELLANEOUS RULES**

1. The provisions of this Agreement shall not be construed to restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit or other allowance now or hereafter accorded either:
 - a) by the laws of a Contracting State in the determination of the tax imposed by that Contracting State;
 - b) by any other special arrangement on taxation in connection with the economic or technical cooperation between the Contracting States.
2. The competent authorities of each Contracting State may prescribe regulations in order to carry out the provisions of this Agreement.

Article 29**MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS**

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30**ENTRY INTO FORCE**

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.
3. The provisions of this Agreement shall have effect in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

Article 31

DURATION AND TERMINATION

This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall continue in force thereafter for a similar period or periods unless either Contracting State notifies the other in writing, six months before the expiry of the initial or any subsequent period, of its intention to terminate this Agreement. In such event, this Agreement shall cease to have effect in both Contracting States in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the respective plenipotentiaries of both Contracting States have signed this Agreement.

DONE at New Delhi on 15th day of June, 2006, corresponding to 19th Jamad al awal, 1427 H, two originals, each in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall

For the Government of the
Republic of India

Sd/—

SHIVRAJ PATIL
Minister of Home Affairs

For the Government of the
State of Kuwait

Sd/—

BADER MISHARI AL-HUMAIHI
Minister of Finance

PROTOCOL

The Republic of India and the State of Kuwait on signing at New Delhi on 15th day of June, 2006, corresponding to 19th Jamad al awal, 1427 H, the Agreement for the Avoidance of Double Taxation with respect of Taxes on Income have agreed upon the following provisions which shall form as integral part of the said Agreement.

In respect of paragraphs 1 and 2 of Article 7, it is understood that when an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein the profits of that permanent establishment shall be determined on the basis of that part of the receipt which is attributable to the actual activity of the permanent establishment for such sales or business. The sales, business or supplies executed outside the Contracting State in which the permanent establishment is situated shall not be taken into consideration in determining the profits of the permanent establishment. Likewise in the case of contracts for survey, constructions or installations, the profits of a permanent establishment shall not be determined on the total amount of the contract, but shall be determined only on the basis of that part of the contract, which is effectively carried out by the permanent establishment in the state where the permanent establishment is situated. The profits related to that part of the contract, which is carried out by the head office of the enterprise shall be taxable only in the state of which the enterprise is a resident.

DONE at New Delhi on 15th day of June, 2006, corresponding to 19th Jamad al awal, 1427 H, two originals, each in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of India

Sd/—

SHIVRAJ PATIL
Minister of Home Affairs

For the Government of the
State of Kuwait

Sd/—

BADER MISHARI AL-HUMAIIDHI
Minister of Finance